



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 26 मार्च, 2003/5 चैत्र, 1925

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 26 मार्च, 2003

संख्या: वि० स०-विधायन-अंतरिम बजट/1-21/2003.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखा अनुदान) विधेयक 2003 (2003 का विधेयक संख्यांक-2) जो आज 4326-राजपत्र/2003-26-3-2003—1,386. (3761) मूल्य : एक रुपया ।

दिनांक 26 मार्च, 2003 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

अजय भण्डारी,
सचिव,
हि0प्र0 विधान सभा ।

हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखा अनुदान) विधेयक, 2003

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

वित्तीय वर्ष 2003-2004 के कुछ भाग के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय धनराशियों के निकालने का उपबन्ध करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखा अनुदान) अधिनियम, 2003 है । संक्षिप्त नाम ।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट से अनधिक धनराशियां जिनका योग 22,15,09,63,000 रुपये (बाईस अरब, पन्द्रह करोड़ नौ लाख तरेसठ हजार रुपये) है, वित्तीय वर्ष 2003-2004 के अप्रैल से जुलाई मास की अवधि में अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं से सम्बन्धित संदायों के विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए निकाली जाए ।

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिए 22,15,09,63,000 रुपये की राशि निकालना ।

3. इस अधिनियम द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से निकाली जाने के लिए प्राधिकृत धनराशियों का विनियोग, अधिनियम की धारा 2 में उल्लिखित अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में अभिव्यक्त प्रयोजनों और सेवाओं के लिए किया जाएगा । विनियोग ।

अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखें)

1 मांग संख्या	2 सेवाएं और प्रयोजन	3 निम्नलिखित राशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा दत्तमत	संचित निधि पर प्रभारित	जोड़
		रुपये	रुपये	रुपये
1	विधान सभा (राजस्व)	1,82,05,000	4,89,000	1,86,94,000
	(पूंजी)	50,00,000	—	50,00,000
2	राज्यपाल और मन्त्रीपरिषद् (राजस्व)	1,21,92,000	47,54,000	1,69,46,000
3	न्याय प्रशासन और (राजस्व)	9,24,92,000	2,03,82,000	11,28,74,000
	निर्वाचन (पूंजी)	43,67,000	—	43,67,000
4	सामान्य प्रशासन (राजस्व)	15,20,66,000	69,65,000	15,90,31,000
	(पूंजी)	10,00,000	—	10,00,000
5	भू-राजस्व (राजस्व)	45,26,15,000	—	45,26,15,000
	और जिला प्रशासन (पूंजी)	4,50,000	—	4,50,000
6	आबकारी और कराधान (राजस्व)	4,86,25,000	—	4,86,25,000
	(पूंजी)	67,000	—	67,000
7	पुलिस और सम्बद्ध (राजस्व)	58,60,15,000	1,33,000	58,61,48,000
	संगठन (पूंजी)	32,33,000	—	32,33,000
8	शिक्षा (राजस्व)	2,82,69,96,000	—	2,82,69,96,000
	(पूंजी)	4,39,48,000	—	4,39,48,000
9	स्वास्थ्य और परिवार (राजस्व)	83,47,48,000	—	83,47,48,000
	कल्याण (पूंजी)	4,99,44,000	—	4,99,44,000
10	लोक निर्माण-भवन (राजस्व)	42,48,62,000	—	42,48,62,000
	(पूंजी)	1,79,00,000	—	1,79,00,000
11	कृषि (राजस्व)	25,18,36,000	—	25,18,36,000
	(पूंजी)	12,09,25,000	—	12,09,25,000
12	उद्यान (राजस्व)	18,29,96,000	—	18,29,96,000
	(पूंजी)	2,58,40,000	—	2,58,40,000
13	सिंचाई और बाढ़ (राजस्व)	27,66,82,000	—	27,66,82,000
	नियंत्रण (पूंजी)	15,89,29,000	—	15,89,29,000
14	पशुपालन, दुग्ध (राजस्व)	21,38,57,000	1,92,000	21,40,49,000
	विकास एवं मत्स्य (पूंजी)	36,69,000	—	36,69,000
15	योजना एवं पिछड़ा (राजस्व)	39,84,80,000	—	39,84,80,000
	क्षेत्र उप-योजना (पूंजी)	6,86,53,000	—	6,86,53,000
16	वन और वन्य जीवन (राजस्व)	1,13,89,14,000	—	1,13,89,14,000
	(पूंजी)	35,33,000	—	35,33,000

1	2	3		
		रुपये	रुपये	रुपये
17	सड़कें और पुल (राजस्व)	75,72,65,000	—	75,72,65,000
	(पूंजी)	64,00,24,000	—	64,00,24,000
18	आपूर्ति, उद्योग और खनिज (राजस्व)	10,55,81,000	—	10,55,81,000
	(पूंजी)	2,33,000	—	2,33,000
19	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (पोषाहार सहित) (राजस्व)	37,42,66,000	—	37,42,66,000
	(पूंजी)	95,57,000	—	95,57,000
20	ग्रामीण विकास (राजस्व)	26,52,48,000	—	26,52,48,000
	(पूंजी)	—	—	—
21	सहकारिता (राजस्व)	3,83,90,000	—	3,83,90,000
	(पूंजी)	1,37,16,000	—	1,37,16,000
22	खाद्य और भाण्डागारण (राजस्व)	3,51,84,000	—	3,51,84,000
	(पूंजी)	38,25,000	—	38,25,000
23	जल और विद्युत (राजस्व)	40,55,13,000	—	40,55,13,000
	विकास (पूंजी)	56,41,67,000	—	56,41,67,000
24	मुद्रण और लेखन सामग्री (राजस्व)	2,82,85,000	—	2,82,85,000
	(पूंजी)	1,67,000	—	1,67,000
25	सड़क और जल परिवहन (राजस्व)	10,27,24,000	—	10,27,24,000
	(पूंजी)	4,00,00,000	—	4,00,00,000
26	पर्यटन और नागर विमानन (राजस्व)	1,17,78,000	—	1,17,78,000
	(पूंजी)	28,33,000	—	28,33,000
27	श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण (राजस्व)	6,59,97,000	—	6,59,97,000
	(पूंजी)	27,34,000	—	27,34,000
28	जलापूर्ति, सफाई, आवास (राजस्व)	91,18,48,000	—	91,18,48,000
	और नगर विकास (पूंजी)	38,82,16,000	—	38,82,16,000
29	वित्त (राजस्व)	1,77,42,08,000	4,63,08,14,000	6,40,50,22,000
	(पूंजी)	3,70,00,000	1,58,85,80,000	1,62,55,80,000
30	विविध सामान्य सेवाएं (राजस्व)	6,00,84,000	—	6,00,84,000
	(पूंजी)	67,12,000	—	67,12,000
31	जनजातीय विकास (राजस्व)	59,51,21,000	—	59,51,21,000
	(पूंजी)	23,89,39,000	—	23,89,39,000
	कुल जोड़ (राजस्व)	15,89,86,54,000	6,25,23,09,000	22,15,09,63,000
	(पूंजी)	13,44,30,73,000	4,66,37,29,000	18,10,68,02,000
	(पूंजी)	2,45,55,81,000	1,58,85,80,000	4,04,41,61,000

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 203 और 204 के अधीन विहित प्रक्रिया के पूर्ण होने तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 206 के साथ पठित अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2003-2004 के अप्रैल से जुलाई माह के लिए अपेक्षित धन के ऐसे व्यय को जो संचित निधि पर प्रभारित हैं और विधान सभा द्वारा यथा दत्तमत अन्य व्यय को पूरा करने के लिए निकालने का उपबन्ध करने के लिए पुरःस्थापित है। मांगे गये धन में वर्ष 2003-2004 की वस्तुतः नई स्कीमों का प्रावधान सम्मिलित नहीं है।

नियमित बजट विधान सभा द्वारा जुलाई, 2003 में पारित किया जाना है। अतः अप्रैल से जुलाई, 2003 के लिए लेखा अनुदान अभिप्राप्त किया जा रहा है।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री।

शिमला :

दिनांक : 26 मार्च, 2003.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[वित्त विभाग, फाईल संख्या वित्त-ए-सी (1)-1/2003]]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखा अनुदान) विधेयक, 2003 की विषय वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 2 of 2003

**THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT)
BILL, 2003**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the services of a part of the financial year 2003-2004.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the State of Himachal Pradesh in the Fifty-fourth Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act, 2003. Short title.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, there may be withdrawn sums not exceeding those specified in column 3 of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Rs. 22,15,09,63,000/- (Twenty two hundred and fifteen crores, nine lakhs and sixty three thousand rupees) only towards defraying the several charges which will come in course of payment during the months of April to July of the financial year 2003-2004 in respect of the services specified in column 2 of the schedule. Withdrawal of Rs. 22,15,09,63,000 from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year 2003-2004.

3. The sums authorised to be withdrawn from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the period mentioned in section 2 of the Act. Appropriation.

THE SCHEDULE
(See sections 2 and 3)

1	2	3		
		Sums not exceeding		
De- mand No.	Services and purposes	Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
		Rs.	Rs.	Rs.
1	Vidhan Sabha (Revenue)	1,82,05,000	4,89,000	1,86,94,000
	(Capital)	50,00,000	—	50,00,000
2	Governor and (Revenue)	1,21,92,000	47,54,000	1,69,46,000
	Council of Ministers (Capital)	—	—	—
3	Administration of (Revenue)	9,24,92,000	2,03,82,000	11,28,74,000
	Justice and Election (Capital)	43,67,000	—	43,67,000
4	General Adminis- (Revenue)	15,20,66,000	69,65,000	15,90,31,000
	tration (Capital)	10,00,000	—	10,00,000
5	Land Revenue (Revenue)	45,26,15,000	—	45,26,15,000
	and District Adminis-(Capital)	4,50,000	—	4,50,000
	tration			
6	Excise and Taxation (Revenue)	4,86,25,000	—	4,86,25,000
	(Capital)	67,000	—	67,000
7	Police and Allied (Revenue)	58,60,15,000	1,33,000	58,61,48,000
	Organisations (Capital)	32,33,000	—	32,33,000
8	Education (Revenue)	2,82,69,96,000	—	2,82,69,96,000
	(Capital)	4,39,48,000	—	4,39,48,000
9	Health and Family (Revenue)	83,47,48,000	—	83,47,48,000
	Welfare (Capital)	4,99,44,000	—	4,99,44,000
10	Public Works- (Revenue)	42,48,62,000	—	42,48,62,000
	Buildings (Capital)	1,79,00,000	—	1,79,00,000
11	Agriculture (Revenue)	25,18,36,000	—	25,18,36,000
	(Capital)	12,09,25,000	—	12,09,25,000
12	Horticulture (Revenue)	18,29,96,000	—	18,29,96,000
	(Capital)	2,58,40,000	—	2,58,40,000
13	Irrigation and Flood (Revenue)	27,66,82,000	—	27,66,82,000
	Control (Capital)	15,89,29,000	—	15,89,29,000
14	Animal Husbandry, (Revenue)	21,38,57,000	1,92,000	21,40,49,000
	Dairy Development (Capital)	36,69,000	—	36,69,000
	and Fisheries			
15	Planning and Back- (Revenue)	39,84,80,000	—	39,84,80,000
	ward area Sub-Plan (Capital)	6,86,53,000	—	6,86,53,000
16	Forest and Wild Life (Revenue)	1,13,89,14,000	—	1,13,89,14,000
	(Capital)	35,33,000	—	35,33,000

1	2	3		
		Rs.	Rs.	Rs.
17	Roads and Bridges (Revenue)	75,72,65,000	—	75,72,65,000
	(Capital)	64,00,24,000	—	64,00,24,000
18	Supplies, Industries (Revenue)	10,55,81,000	—	10,55,81,000
	and Minerals (Capital)	2,33,000	—	2,33,000
19	Social Security and (Revenue)	37,42,66,000	—	37,42,66,000
	Welfare (including (Capital)	95,57,000	—	95,57,000
	Nutrition)			
20	Rural Development (Revenue)	26,52,48,000	—	26,52,48,000
	(Capital)	—	—	—
21	Co-operation (Revenue)	3,83,90,000	—	3,83,90,000
	(Capital)	1,37,16,000	—	1,37,16,000
22	Food and Ware (Revenue)	3,51,84,000	—	3,51,84,000
	housing (Capital)	38,25,000	—	38,25,000
23	Water and Power (Revenue)	40,55,13,000	—	40,55,13,000
	Development (Capital)	56,41,67,000	—	56,41,67,000
24	Printing and (Revenue)	2,82,85,000	—	2,82,85,000
	Stationery (Capital)	1,67,000	—	1,67,000
25	Road and Water (Revenue)	10,27,24,000	—	10,27,24,000
	Transport (Capital)	4,00,00,000	—	4,00,00,000
26	Tourism and Civil (Revenue)	1,17,78,000	—	1,17,78,000
	Aviation (Capital)	28,33,000	—	28,33,000
27	Labour, Employ- (Revenue)	6,59,97,000	—	6,59,97,000
	ment and Training (Capital)	27,34,000	—	27,34,000
28	Water Supply, (Revenue)	91,18,48,000	—	91,18,48,000
	Sanitation, Housing (Capital)	38,82,16,000	—	38,82,16,000
	and Urban Develop- ment			
29	Finance (Revenue)	1,77,42,08,000	4,63,08,14,000	6,40,50,22,000
	(Capital)	3,70,00,000	1,58,85,80,000	1,62,55,80,000
30	Miscellaneous (Revenue)	6,00,84,000	—	6,00,84,000
	General Services (Capital)	67,12,000	—	67,12,000
31	Tribal Development (Revenue)	59,51,21,000	—	59,51,21,000
	(Capital)	23,89,39,000	—	23,89,39,000
	Grand Total	15,89,86,54,000	6,25,23,09,000	22,15,09,63,000
	(Revenue)	13,44,30,73,000	4,66,37,29,000	18,10,68,02,000
	(Capital)	2,45,55,81,000	1,58,85,80,000	4,04,41,61,000

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of clause (1) of article 204 read with article 206 of the Constitution of India to provide for withdrawal from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the moneys required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and other expenditure as voted by the Legislative Assembly for the months of April to July, 2003 of the Financial year 2003-2004 pending the completion of the procedure prescribed in articles 203 and 204 of the Constitution of India. The moneys demanded do not include the provision for the Really New Schemes for the year 2003-2004.

The regular Budget is to be passed by the Legislative Assembly in July, 2003. As such the vote on account is being obtained for April to July, 2003.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SHIMLA :

The 26th March, 2003.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE
CONSTITUTION OF INDIA

[FINANCE DEPARTMENT FILE NO. FIN. A-C. (1)-1/2003]

The Governor, Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the proposed Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Bill, 2003, recommends, under Article 207 of the Constitution of India the introduction in and consideration by the Legislative Assembly of the said Bill.